

मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर रिफाइनरी कार्मिकों में उत्साह दिखा

श्रमिकों के साथ मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाई

बालोतरा, 10 जनवरी (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को बालोतरा जिले में पंचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया एवं समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, राज्य सरकार एवं रिफाइनरी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बस में बैठ कर रिफाइनरी के विकास कार्यों का निरीक्षण किया।

लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी परिसर में ड्यूटी फीड क्रेकर यूनिट का अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस यूनिट के निर्माण में बुजुर्ग खलीफा से



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पंचपदरा में एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के साथ बातचीत भी की।

कार्यों में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि रिफाइनरी और आस-पास के क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें।

मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को एक विशेषाधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए, जो कि 15 दिन में रिफाइनरी परियोजना के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट बनाए।

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के मॉडल का अवलोकन भी किया और रिफाइनरी परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के.के. विश्वा, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक हमीर सिंह भायल, आदुराम मेघवाल, प्रियंका चौधरी, अरुण चौधरी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग एवं वाणिज्य अजिताम शर्मा, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकांत, रीको प्रबन्ध निदेशक इन्द्रजीत सिंह, एच.आर.आर.एल. के निदेशक एस. भारतन, सीईओ कमलाकर आर विखर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

‘मस्जिद के समीप के कुएं पर यथास्थिति बनाए रखें’

■ सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाहीजामा मस्जिद के कुएं पर नगर पालिका के नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है।

नयी दिल्ली, 10 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर, विवादित संभल मस्जिद के पास के कुएं का इस्तेमाल करने के लिए स्थानीय नगर पालिका की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस को 21 फरवरी, 2025 तक लागू नहीं करने और दो सप्ताह में स्थिति का विवरण पेश करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने संभल शाही जामा मस्जिद समिति की याचिका पर यह आदेश पारित किया। पीठ ने संभल नगर पालिका अधिकारियों से कहा कि वे पोस्टरों के माध्यम से जारी किए गए अपने सार्वजनिक नोटिस को लागू न करें, जिसमें शाही जामा मस्जिद के पास के कुएं को हरि मंदिर का कुआं बताया गया है तथा वह श्रद्धालुओं की पूजा व स्नान के लिए बनाया गया था।

श्रीष अदालत के समक्ष राज्य सरकार ने कहा कि उस जगह के आसपास की स्थिति शांतिपूर्ण थी, लेकिन आवेदक ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। इस पर मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि नगर पालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस में स्नान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि मातृ भाषा में शिक्षा मिलने के कारण सिर्फ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि राजस्थान अपनी संस्कृति भी खोता जा रहा है क्योंकि भाषा के लुप्त होने की वजह से हजारों सालों के अनुभव और समृद्ध संस्कृति का ह्रास होता है। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था।

दिल्ली के बाकी प्रत्याशी तय करने के लिए भाजपा की बैठक

नयी दिल्ली, 10 जनवरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केन्द्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की शुक्रवार देर शाम यहां पार्टी मुख्यालय पर एक अहम बैठक बुलाई गयी, जिसमें बाकी उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लिये जाने की उम्मीद है।

पार्टी दिल्ली की 70 विधान सभा सीटों में से 29 के लिए उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नयी विधान सभा के चुनाव की गजट अधिसूचना आज जारी हो चुकी है और नामांकन 17 जनवरी तक दाखिल किए जाएंगे। भाजपा सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री

■ मोदी, अमित शाह, राजनाथ व नड्डा भी बैठक में शामिल हुए।

राजनाथ सिंह के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में दिल्ली विधानसभा की बाकी बची सीटों के लिए उम्मीदवार तय किए जाएंगे। भाजपा द्वारा अब तक घोषित 29 प्रत्याशियों में बाहरी दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का भी नाम है। पार्टी ने वर्मा को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उतारा है।

‘ई-सिगरेट की बिक्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसे हैरानी हुई कि राजस्थान सरकार की क्राइम ब्रांच ने इन सबालों के जवाब देने के लिये कोई भी रिकॉर्ड बरकरार नहीं रखा है, इससे साबित होता है कि राज्य सरकार इससे बेपरवाह है।

अदालत ने कहा कि इस मामले में कई दस्तावेज रिकॉर्ड पर हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार को बार-बार कहा गया कि ई-सिगरेट रोकने के लिये कार्यवाही करें, लेकिन इसे रोकने के लिये केवल कागजी कार्यवाही की गई है। अदालत ने कहा कि कमिश्नर के 2022 में दायर शपथ पत्र से ये ही जाहिर होता है कि ई-सिगरेट की बिक्री रोकने के लिये विभाग कोई मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस विभाग की अपनी सीमाएं हैं। अदालत ने कहा कि चूंकि शपथ पत्र दायर किये काफी समय हो गया है, उन्हें नया शपथ पत्र पेश करना होगा। अदालत ने कहा कि अगली तारीख पर जो अफसर ई-सिगरेट की बिक्री को मॉनिटर करने के लिये नियुक्त किये जायें, वे वी.सी. के जरिये अदालत में उपस्थित रहें। इस मामले में अगली तारीख 1 फरवरी 2025 तय की गई है।

अश्विन अब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जाने गंवाई। पुराने लोग याद करते हैं कि तब राज्य में कांग्रेस सरकार थी, हिंदी सम्बंधी फैसले ने राज्य में कांग्रेस को खलनायक बना दिया और उसके बाद द्रविड़ पार्टियां सत्तारुढ़ हुईं और तब से लेकर आज तक कांग्रेस अपने दम पर राज्य में पुनः सत्ता में नहीं आ पाई है।

कांग्रेस को राज्य में किसी न किसी द्रविड़ पार्टी के साथ गठबंधन करना ही पड़ता है, कभी द्रमुक से, तो कभी अनाद्रमुक से। फिलहाल दो दशक से कांग्रेस का द्रमुक से गठबंधन है।

अश्विन की टिप्पणी से तमिलनाडु में उनके प्रशंसक अवश्य बढ़ गए होंगे।

ट्रम्प पहले अमरीकी राष्ट्रपति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुक्त होकर व्हाइट हाउस जा सकेंगे। अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पॉन स्टार को पैसे देकर चुप रहने के लिए मजबूर करने के अपराध में दोषी करार दिया गया था। ट्रंप एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति (वर्तमान या पूर्व) हैं, जिन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रम्प की ओर से कार्यवाही को रोकने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। इसी के साथ, मैनहट्टन में न्यूयॉर्क राज्य की अदालत में सजा सुनाने का रास्ता खुल गया था।

ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्हें सजा सुनाया जाना एक ऐसा आश्चर्यजनक विरोधाभास पैदा करता है, जिसका गवाह अमेरिका पहले नहीं है। कुछ ही दिनों में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की विशाल शक्तियां और देश के कानूनों और संविधान के अंतिम संरक्षक बनने वाले हैं।